नवल टाइम्स

RNI No. UTTHIN/2012/42590

भारत सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त

वर्ष : 14 अंकः 24 हिन्दी साप्ताहिक हरिद्वार, बृहस्पतिवार 03 जुलाई 2025 मूल्यः 1 रूपया पृष्ठः 4

धामी कैबिनेट ने रेशम कोकून की एमएसपी में की बढ़ोत्तरी

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक प्रस्ताव पर मुहर लगी है। दरअसल, हर साल रेशम कोकून की एमएसपी तय की जाती है। इसी क्रम में इस साल भी रेशम विभाग ने कोकून की नई एमएसपी का प्रस्ताव तैयार किया था, जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। पिछले साल कोकून के लिए तय की गई एमएसपी में इस साल बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके तहत हाई क्वालिटी के कोकून की कीमत को 400 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 440 रुपए प्रति किलो किया गया है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में एक ही प्रस्ताव पर मुहर लगी है। जिसमें कृषि विभाग के तहत सिल्क के कोकून की नई एमएसपी तय की गई है। हालांकि, हर साल कोकून की एमएसपी तय की जाती है, जिसके क्रम में इस साल भी कोकून की नई दरें तय की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कोकून की दरों में बढ़ोतरी की गई है। इससे प्रदेश में सिल्क के उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वर्तमान समय में प्रदेश के दो जिलों देहरादून और बागेश्वर

में मुख्य रूप से कोकून का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन सरकार के इस प्रोत्साहन से आने वाले समय में कोकून के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी।

मंत्री जोशी ने कहा कि सिल्क की क्वालिटी काफी बेहतर है। क्योंकि उत्तराखंड के कोकून से बनी सिल्क की साड़ियों की डिमांड न सिर्फ प्रदेश में बढ़ी है, बल्कि अन्य राज्यों में भी काफी अधिक पसंद की जा रही है। क्योंकि तमाम जगहों पर एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड के सिल्क साड़ियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। जिसके चलते टर्नओवर

O ए ग्रेड के कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर की गई 440 रूपए प्रति किलो

O दो जिलों देहरादून और बागेश्वर में मुख्य रूप से कोकून का उत्पादन किया जा रहा

बढ़ता जा रहा है। किसानों को कोकून के बीज समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोकून का बीज किसानों को समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।

ए ग्रेड के कोकून की कीमत 400 से बढ़ाकर 440 रुपए प्रति किलो की गई, बी ग्रेड के कोकून की कीमत 370 से 395 रुपए प्रति किलो की गई, सी ग्रेट के कोकून की कीमत 280 से 290 रुपए प्रति किलो की गई, डी ग्रेट के कोकून की कीमत 230 से बढ़कर 240 रुपए प्रति किलो की गई।

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर आईएमए ने किया कार्यक्रम का आयोजन

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर आईएमए की और से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में डा.आर.के. सिंघल, डा.संजय शाह, डा.मनोज सिंह को चिकित्सा क्षेत्र में उनकी सेवा व विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही बारहवीं की परीक्षा में 98.8 फीसदी अंक प्राप्त करने पर डा.आलोक व डा.सोनाली वशिष्ठ की पुत्री हिमान्या वशिष्ठ को भी सम्मानित किया गया। आईएमए हरिद्वार शाखा के अध्यक्ष डा.विकास दीक्षित ने कहा कि भारत रत्न डा.बीसी रॉय के सम्मान में चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डा.विकास दीक्षित ने कहा कि डा.बीसी रॉय का जीवन सम्पूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मुख्य अतिथी सीएमओ डा.आर.के. सिंह ने कहा चिकित्सक सेवा भावना से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आईएमए के वरिष्ठ सदस्य डा.विपिन मेहरा ने चिकित्सकों की समस्याओं व उनके निवारण के विषय में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन सचिव डा.विमल कुमार व कोषाध्यक्ष डा.अश्विनी चौहान ने किया। विशिष्ट अतिथी उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष डा.प्रवीन जिंदल, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष डा.अनुज सिंघल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में डा.कैलाश पांडे, डा.एन.के. अग्रवाल, डा.नीता मेहरा, डा.यतींद्र नागयान, डा.नीता नागयान, डा.बीके एंडले, डा.पीके मालशे, डा.सुशील, डा.विनीता कुमार, डा.मुकेश, डा.अंजली मिश्रा, डा.जसप्रीत सिंह, डा.मनप्रीत कौर, डा.एसके मिश्रा, डा.दीपक कुमार, डा.अन्नू लूथरा, डा.रविन्द्र, डा.अलका गोयल, डा.अंजुल श्रीमाली, डा.विजय वर्मा, डा.प्रकाश बेंजावल, डा.राहुल आहर, डा.नेहा शर्मा, डा.गरिमा सिंह, डा.सुमंतु विरमानी मौजूद रहे।

आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों को सीईओ के सख्त निर्देश

देहरादून । राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड: आयुष्मान योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को अब लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक वार्ड में योजना के टोल फ्री नंबर डिस्पले करने, आईसीयू के निकट वेटिंग रूम बनाने समेत कई जरूरी कदम उठाने होंगे।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने सभी अस्पतालों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को अस्पताल में किसी तरह की दिक्कत ना हो इस पर प्राधिकरण की ओर से बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है। जिसमें तमाम तरह की फीडबैक मिल रही हैं। प्राधिकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने बताया कि जनकल्याण की इस योजना का समुचित लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे, यह प्राथमिकता है। कई बार अस्पतालों में लाभार्थियों को भ्रमित करने या उपचार के नाम पर धन वसूली की सूचनाएं मिलती है। इसकी रोकथाम के प्रयास किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि सूचीबद्ध अस्पतालों को अपने परिसर में आयुष्मान योजना से संबंधित जानकारियों के डिस्पले बोर्ड लगाने होंगे। साथ ही प्रत्येक वार्ड में प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर चस्पा करने होंगे, जिसमें हिंदी और स्थानीय भाषा में स्पष्ट लिखा हो कि कोई भी समस्या हो तो चस्पा किए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। उन्होंने बताया कि कुछ संस्थानों में आईसीयू के वेटिंग रूम व पार्किंग जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं। अस्पतालों को आईसीयू के निकट ही वेटिंग रूम की व्यवस्था देने को कहा गया है। वहीं कतारों से निजात के लिए टोकन डिस्पले लगाने, प्रतीक्षा कक्ष की समुचित व्यवस्था व मरीज के फीडबैक फार्म को भी अनिवार्य कर दिया गया है। एबीडीएम की सुविधाओं का उपयोग करने, स्कैन एंड शेयर व आभा आईडी के बारे में जानकारी देने के भी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। सीईओ ने कहा कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुचारू होने की जानकारी अस्पताल प्रशासन को निर्धारित समय में देनी होगी।

सूबे के नर्सिंग कॉलेजों में पूर्व की भांति रहेगी प्रवेश प्रक्रिया

विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय

देहरादून(नवल टाइम्स)। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर के राजकीय एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया इस बार भी पूर्व की भांति आयोजित की जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दे दिये गये हैं। साथ ही एच.एन.बी. चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दी गई है जो भविष्य में नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के लिये आईएनसी गाइडलाइन के अनुरूप ठोस प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगी। सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज दून मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर बैठक का आयोजन किया गया जिसमे चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन, निजी नर्सिंग कॉलेज एसोशिएसन के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें विभागीय मंत्री ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू न किये जाने पर विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन को आडेघ् हाथ लिया। उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुये विश्वविद्यालय प्रशासन व शासन के

अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि छात्रों के भविष्य के लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में नर्सिंग कॉलेज के एसोशिएसन के पदाधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के तहत निजी कॉलेजों की 50 फीसदी सीटें भी भर पाना संभव नहीं है। लिहाजा पूर्व की भांति 50 फीसदी सीटें निजी संस्थान संचालकों को एसोसिएशन के माध्यम से भरने की अनुमति दे दी जाय। शेष 50 फीसदी सीटें विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के तहत आवंटित की जाय। इसके बावजूद रिक्त रहने वाली सीटों को भरने की अनुमति भी एसोसिएशन को दी जाय। जिस पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ओकांर सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के उपरांत तीन काउंसिलिंग के उपरांत भी रिक्त रहने वाली सीटों को निजी संस्थान न्यूनतम अर्ह शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप स्वयं भर सकते हैं यह व्यवस्था नर्सिंग पाठ्यक्रम के अधिनियम में विद्यमान है। दोनों पक्षों को सुनने बाद विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित किया कि समय की बाद्धता को देखते हुये इस बार भी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व की भांति आयोजित की जाय ताकि समय रहते सरकार एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जा सके। जबकि अगले शैक्षणिक सत्र के लिये नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी व सुलभ बनाया जायेगा, जिसके लिये मेडिकल विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें दो सदस्य निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के भी शामिल किये जायेंगे। समिति की रिपोर्ट व आईएनसी की गाइडलाइन के आधार पर शासन प्रवेश प्रक्रिया के लिये अपने स्तर से नई गाइडलाइन जारी करेगा। बैठक में सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार, एच.एन.बी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, कुलसचिव मेडिकल विश्वविद्यालय डॉ. आशीष उनियाल, राजिस्ट्रार नर्सिंग काउंसिल मनीषा ध्यानी, निजी नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारी व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पादकीय

ई-वोटिंग का दौर

ई-वोटिंग वैसे तकनीक के दौर में नया नहीं रह गया है। विभिन्न कंपनियां अपने उत्पादों को लेकर जनता की राय जानने के लिए ऐसा करती आई हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में हमने नेताओं की डिजिटल रैलियों तक को देखा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ई-वोटिंग की दिशा में हम आखिर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बिहार के प्रयोग को इसकी शुरुआत माना जा सकता है। पिछले आम चुनावों में बुजुर्गों व शारीरिक रूप से अशक्त लोगों को उनके घर जाकर मतदान कराने की सुविधा दी गई थी। हमारे यहां पोस्टल वोटिंग का प्रावधान भी है। ई-वोटिंग को इन सुविधाओं का विस्तारित और आधुनिक रूप ही कहा जा सकता है। आज जब इंटरनेट व बिजली की सुविधा दूर-दराज तक पहुंच गई है। ई-वोटिंग को पूरी तरह नहीं तो चरणबद्ध रूप से लागू किया जा सकता है। इससे मतदाताओं के समय व श्रम की बचत तो होगी ही, लोकतंत्र के महायज्ञ कहे जाने वाले चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी संभव हो सकेगी। वैसे भी भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है कि प्रत्येक मतदाता को मतदान करने का मौका मिले। यह तर्क जरूर दिया जाता रहा है कि भारत में अभी मतदाता तकनीकी रूप से इतने सक्षम नहीं है कि ई-वोटिंग की प्रक्रिया समझ सके। मोबाइल एप पर पंजीकरण से लेकर पहचान व लॉग -इन तक की प्रक्रिया में भी संदेह इस बात का भी व्यक्त किया जाता है कि दुरुपयोग व फर्जीवाड़ा यहां भी संभव है। लेकिन हर समस्या का समाधान भी तलाशा जा सकता है। ईवीएम के जरिए मतदान शुरू हुआ तब भी कई सवाल उठे थे। ये सवाल अब भी उठ रहे हैं लेकिन ईवीएम के विश्वसनीय न होने को लेकर ठोस प्रमाण आज तक समाने नहीं आए हैं। मोट तौर पर देश चुनावों को लेकर साल-दर-साल बढने़ वाले खर्च को बचाने व चरणों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया को रोकने के लिए ई-वोटिंग बेहतर उपाय हो सकता है। ऑनलाइन वोटिंग असंभव कतई नहीं है। जरूरत सही तकनीक का इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से लागू करने की है।मतदान के प्रति बेरुखी हमारे देश में कोई आज की समस्या नही है। यह बात सच है कि पिछले वर्षों में देश में होने वाले विभिन्न स्तर के चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ा ही है फिर भी हम हर मतदाता को मतदान केन्द्रों तक लाने में सफल नहीं हो पाए हैं।

गुरु की आवश्यकता अपरिवर्तनीय

डॉ.संजय कुमार पाठक

महर्षि वेद व्यास ने महाभारत, पुराणों और भारतीय ज्ञान-परंपरा को संरचित किया, वे गुरु परंपरा के मूल प्रतीक हैं। उनकी भूमिका मात्र ज्ञान देने की नहीं, बल्कि धर्म, नीति, चेतना और सामाजिक संतुलन स्थापित करने की थी। वहीं दूसरी ओर आज का युग एआई (आर्टिफिशियल इंटलीजेंस या कृत्रिम बुद्धमत्ता) का है जहाँ एक क्लिक करते ही ज्ञान का भंडार उपलब्ध है, लेकिन वह ज्ञान प्रेरणा नहीं बन पाता, दृष्टि नहीं देता, और जीवन का मार्गदर्शन नहीं करता। महर्षि वेद व्यास से लेकर एआई तक गुरु की भूमिका कैसे बदली? क्या बदलनी चाहिए? और क्या नहीं बदलनी चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर हमें उस संक्रमणकालीन यात्रा में मिलेगा जो व्यास से शुरू होती है और एआई तक पहुँचती है।

मुगल आक्रांता महमूद गजनवी के साथ 1017 में भारत आए अलबरूनी ने अपने संस्मरण 'किताब-उल-हिन्द' में लिखे। इसमें अलबरूनी ने लिखा कि मैंने अपने भारत-भ्रमण के दौरान वहाँ के हिंदुओं में तीन विशेषताएँ देखीं, पहला वहां का हिन्दू झूठ नहीं बोलता, दूसरा उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता और तीसरा उसे अपनी ज्ञान परम्परा और शास्त्रों पर अगाध विश्वास है। हम सभी के अनुभव में भी आता है कि अब तीनों ही परिस्थितियां विपरीत हो चुकी हैं। समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों का आधिकारिक रूप से बीजारोपण 1835 में मैकाले ने अपनी विषाक्त शिक्षा प्रणाली के माध्यम से किया था। उसने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से समाज के मानस में EEE (English, Education, Employment) फार्मूले को प्रतिस्थापित कर दिया, जिसके फलस्वरूप संस्कृत, संस्कार और गुरुकुल जैसी भारत की मूल शिक्षा परंपराएँ धीरे-धीरे अप्रासंगिक होती चली गईं। शिक्षा का उद्देश्य युक्तकरी से हटकर केवल नियुक्तिकरी बन गया। आज़ादी के बाद यह स्थिति और विकृत हो गई, मैकाले की सोच में मदरसे और मार्क्स की विचारधारा भी जुड़ गई, जिससे भारतीय समाज के स्व का भाव विलोपित होता गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपराओं को भूलकर हीनभावना से ग्रस्त हो गया।

भारत केवल एक भू-भाग नहीं, बल्कि अध्यात्म का पर्याय है। यदि भारत को पुन: भारत बनाना है, तो हमें अपनी हजारों वर्षों पुरानी जड़ों से जुड़ना होगा। इसके लिए गुरु-शिष्य परंपरा, संस्कृत, गुरुकुल, परिवार, समाज और शिक्षा इन सभी संस्थाओं का गहन परिष्कार अनिवार्य है। जब हर प्रश्न का उत्तर इंटरनेट और एआई से मिलने लगा है, तब गुरु की आवश्यकता पर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है, परंतु इसके प्रत्युत्तर में यह भी स्पष्ट है कि एआई सूचना दे सकता है पर बोध नहीं, वह तथ्य बता सकता है किन्तु सत्य का बोध नहीं करा सकता। एआई ज्ञान दे सकता है पर विवेक नहीं। गुरु तो ज्ञान को दृष्टि में बदलता है और दृष्टि को जीवन में उतारता है। एआई युग में गुरु की भूमिका अब चेतना के संरक्षक के रूप में और भी महत्वनपूर्ण हो गई है। वर्तमान शिक्षा में चरित्र निर्माण का तत्व गौण हो गया है। बचपन से ही बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा, रैंक, करियर और सफलता की भाषा सिखाई जा रही है, जबकि संयम, सहनशीलता, आदर, विनम्रता जैसे मूल्य धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। गुरु की पुनर्प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संस्कारों के बिना शिष्य गुरु को समझ नहीं सकता और बिना श्रद्धा के गुरु का प्रभाव नहीं बनता। आज का छात्र शिक्षा को सेवा नहीं, बल्कि उत्पाद मानने लगा है। फीस देने के बाद ज्ञान का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मांगने वाला समाज, गुरु को आचार्य नहीं, सेवाप्रदाता मान बैठा है। जब तक शिक्षा व्यवसाय बनी रहेगी, तब तक छात्र और शिक्षक के बीच श्रद्धा का सेतु नहीं बन सकेगा। श्रद्धा तभी जागती है जब शिक्षक केवल ज्ञान नहीं, जीवन दर्शन भी साझा करता है।

राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रत्तर

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रत्तर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कशमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केंद्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुराग्रहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।

हिन्दी को हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी मंज पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मानुष की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है।

भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है।

फडणवीस सरकार की ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों की निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के लिए जाना जाता था, पर इधर तीखे हिंदी विरोध में कर्नाटक के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों को अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सबक लेंगे हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि इसके लिये बनी समितियों में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएग और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हासिल हो जाएगी।

महाराष्ट्र में बढ़ते हिन्दीभाषियों के अनुपात को देखते हुए देर-सबेर हिन्दी को अपनाना ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र, कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात हिन्दी के पक्ष में है। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9 प्रतिशत और मराठीभाषियों की 42.9 प्रतिशत थी जो 2011 में क्रमश: 30.2 प्रतिशत और 41 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76 प्रतिशत से 73.4 प्रतिशत पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। इसीलिये हिंदी लादने के इस फैसले ने न केवल उद्धव और राज ठाकरे को आक्रामक रूप में सामने ले आई बल्कि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सुर में सुर मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी हौसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी।

हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर परोक्ष रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है। ये लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इनकी भाषा को दोयम दर्जे का माना जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा 'एकता में अनेकता' के विपरीत है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी और मराठी दोनों को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है और मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा। किसी भी राज्य में भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर दूसरी भाषाओं को अपमानित करना न तो संवैधानिक है और न ही नैतिक। भाषायी सह-अस्तित्व के लिये महाराष्ट्र में मराठी को सर्वोच्च स्थान मिले, लेकिन हिंदी भाषा को भी सम्मान मिले, यह संतुलन ही स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। स्कूलों में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी- तीनों भाषाओं को समुचित महत्व देकर बच्चों में बहुभाषिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल भाजपा एवं केन्द्र सरकार को घेरने के लिये जिस तरह भाषा, धर्म एवं जातियता को लेकर आक्रामक रवैया अपनाते हुए देश में अशांति, अराजकता एवं नफरत को फैला रहे रहे हैं, यह चिन्ताजनक है। महाराष्ट्र में हिन्दी का विरोध आश्चर्यकारी है। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बावजूद हिन्दी को उसका उचित स्थान न मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

बिग ब्यूटीफुल बिल बना ट्रंप के लिए जी का जंजाल

डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्तावित बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिकी संसद में तूफान खड़ा हो रहा है। इसे ट्रंप प्रशासन की दूसरी पारी का ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। जो उनके चुनावी वादों को पूरा करने के रूप में देखा जा रहा है। इस बिल के पीछे की सच्चाई और इसके संभावित परिणामों को लेकर अमेरिका तथा भारत जैसे देशों के लिए इस बिल के परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स कटौती, सीमा सुरक्षा, और सामाजिक योजनाओं में बदलाव के ज्यादा अधिकार राष्ट्रपति को देता है। इसमें सरकार द्वारा 2017 के टैक्स कट्स को स्थायी करने, व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कमी करने ओवरटाइम व टिप्स पर टैक्स छूट जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस बिल में बॉर्डर, अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन के लिए 4.5 ट्रिलियन डॉलर का भारी-भरकम खर्च प्रस्तावित है। दूसरी ओर सरकार मेडिकेड और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाओं में कटौती कर सकती है। जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग को भारी नुकसान होना तय है। भारत एवं भारतीयों के लिए सबसे चिंताजनक विदेशी धन-प्रेषण पर 3.5 से 5त्न टेक्स भारतीय-अमेरिकी समुदाय को सीधे प्रभावित करेगा। भारत को भेजे जाने वाले धन पर यह टैक्स भारतीय रुपये को और भी कमजोर कर सकता है। जिसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बिल उनके धनाढ्य समर्थकों और पूंजीपतियों के लिए को फायदा पहुंचाने का बिल माना जा रहा है। भारत में जिस तरह से इलेक्ट्रोल बांड के माध्यम से राजनैतिक दलों के लिये बिल लाया गया था, इस बिल के माध्यम से मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चंदा मिला। चंदे के आधार पर ठेके दिये गए। बिग ब्यूटी बिल के माध्यम से ट्रम्प को जो अधिकार मिलेंगे, उससे वह चंदा और परिवार के निजी कारोबार को बढ़ाने के लिये उपयोग करेंगे। यह आशंका अमेरिका में व्यक्त की जा रही है। डेमोक्रेट्स इसे अमीरों का बिल बता रहे हैं। वहीं रिपब्लिकन भी अमेरिका के ऊपर बढ़ते कर्ज जो 2.4 से 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, उसको लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स ने इस बिल को भ्रष्ट वित्त प्रणाली का प्रतीक बताया है। उनका कहना है राष्ट्रपति ट्रंप अपने अरबपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस बिल को पास कराने जा रहे है। राष्ट्रपति और ट्रंप के पूर्व सहयोगी एलन मस्क ने भी इसका विरोध किया है। इस विरोध के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तकरार बढ़ी है। एलन मस्क ने धमकी दी है, वह अमेरिका में तीसरी पार्टी बनाएंगे। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिका से बाहर निकालने तक की बात कह दी है। भारत के लिए यह बिल बिग एंड बैड साबित हो सकता है।

भारत सरकार की खामोशी हैरान करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस बिल के बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनकी चुप्पी से यह धारणा बनने लगी है, भारत अमेरिकी दबाव के सामने नतमस्तक है गौतम अडानी जैसे कारोबारियों के हितों की रक्षा में क्या भारत सरकार राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर रही है यह बिल अमेरिकी संसद में पारित होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका दूरगामी दुष्प्रभाव होगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने ऋषिकुल परिसर के निदेशक कार्यालय में की तालाबंदी

चिकित्सक भी आए समर्थन में, 2 घंटे ओपीडी बंद करने का किया ऐलान

हरिद्वार(नवल टाइम्स)। वेतन संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ऋषिकुल और गुरूकुल आयुर्वेदिक चिकित्सालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने बुधवार को ऋषिकुल परिसर में निदेशक कार्यालय पर तालाबंदी और कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। ऋषिकुल चिकित्सालय के चिकित्सक और प्रोफेसर भी कर्मचारियों के बीच पहुंचे और आंदोलन का समर्थन करते हुए बृहष्पतिवार से 2 घंटे ओपीडी बंद रखने और कक्षाएं नहीं लेने का ऐलान किया। कुल सचिव डा.ओपी सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को बताया कि उनकी प्रमुख सचिव वित्त, सचिव आयुष, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलपति, से वार्ता हुई है। वार्ता में वेतन जारी करने पर सहमति बनी है। लेकिन वेतन कितने दिन में आएगा और कितना आयेगा। इसके लिए 15 तारीख तक इंतजार करना होगा।

धरना प्रदर्शन को संबोधित करने हुए डा.संजय त्रिपाठी एवं डा.प्रवेश तोमर, डा.अंजली ने कहा कि जब तक वेतन खातों में नहीं आता तब तक कक्षाओं और प्रतिदिन 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार रहेगा। जल्द स्थाई समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा, आयुर्वेद एवं यूनानी कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री केके तिवारी, आयुर्वेदिक फार्मेसी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार और मंत्री प्रिंस ने कहा कि हरिद्वार आने वाले जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर उन्हें भी कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत कराया जाएगा। उप शाखा अध्यक्ष छत्रपाल सिंह, उपाध्यक्ष ताजबर सिंह, अनिल कुमार, अजय कुमार ने कहा कि समाधान के तौर पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान कोषागार से किया जाए, या फिर उन्हें निदेशक आयुर्वेदिक यूनानी सेवाएं उत्तराखंड देहरादून के अंतर्गत समायोजित कर दिया जाए।

धरना प्रदर्शन में दिनेश लखेडा, डा.संजय त्रिपाठी, डा.प्रवेश तोमर, छत्रपाल सिंह, ताजबर सिंह, डा.अंजली, डा.सीमा, डा.कीर्ति, अनिल कुमार, लोकेंद्र, ज्योति नेगी, मनोज पोखरियाल, सुमंत पाल, डा.शैलेन्द्र, डा.शशिकांत तिवारी, मनीष पंवार, राकेश कुमार, सुदेश कुमार, सतीश, बाला देवी, नीलम बिष्ट, पुष्पा, ममता पाल, कमलेश, ईशा, विमला देवी, कैलाशो, ब्रिजेश, अंकित, राजू कश्यप, विनोद कुमार, अरूण कुमार, पप्पू, सहदेव, दीपक आदि शामिल रहे।

अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने किया कांवड़ मेले में फूड लाइसेंस अनिवार्य किए जाने के सरकार के निर्णय का स्वागत

हरिद्वार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कांवड़ मेले के दौरान फूड लाइसेंस अनिवार्य किए जाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का स्वागत किया है। श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदू हृदय सम्राट हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। सावन में होने वाले कांवड़ मेले में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी सहित तमाम राज्यों से करोड़ों शिवभक्त हरिद्वार आते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष कांवड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं कांवड़ियों के पैर धोकर और हैलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत करते हैं। कांवड़ मेले के दौरान किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। इसके लिए फूड लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। फूड लाइसेंस और दुकानदार की पहचान स्पष्ट होने से किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि सभी को कांवड़ मेला संपन्न कराने में सरकार और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

रुड़की (नवल टाइम्स)। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की (आईआईटी रुड़की) ने भारतीय विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, नवाचार एवं क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

विद्युत मंत्रालय, सीईए एवं आईआईटी रुड़की के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस समझौता ज्ञापन पर बीते मंगलवार को हस्ताक्षर किए गए। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य आईआईटी रुड़की की शैक्षणिक और शोध क्षमताओं को सीईए की तकनीकी और विनियामक विशेषज्ञता के साथ समन्वित करना है, ताकि विद्युत क्षेत्र में प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जा सके और भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सहायता की जा सके। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, दोनों संस्थान विद्युत प्रणाली नियोजन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड विश्वसनीयता एवं लचीलापन, तथा ऊर्जा भंडारण पर केंद्रित संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेंगे; साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए तकनीकी अध्ययन और नीति विश्लेषण करेंगे; सेमिनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप एवं कार्यशालाओं जैसे ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे; विद्युत प्रणाली विश्लेषण और दीर्घकालिक नियोजन के लिए तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर विकसित करेंगे; सीईए एवं अन्य विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं के व्यावसायिकों के लिए अनुकूलित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद ने ऊर्जा क्षेत्र में टिकाऊ एवं नवीन समाधान प्राप्त करने में शिक्षा-सरकार सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रो. के.के. पंत ने राष्ट्रीय विकास में योगदान देने की संस्थान की विरासत पर गर्व व्यक्त किया और विद्युत क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा व्यावसायिकों के कौशल विकास में इस साझेदारी के महत्व पर बल दिया। यह समझौता ज्ञापन भारत की ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप स्वच्छ, अधिक विश्वसनीय और आत्मनिर्भर विद्युत प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों में कार्यों के लिए ई-डीपीआर मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने राज्य एवं जनहित से जुड़ी योजनाओं सहित राज्य सरकार के कर्मियों की समस्याओं एवं मुद्दों पर चर्चा करते हुए विभिन्न दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने विभागों के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के लिए ई-डीपीआर मॉड्यूल को लागू किए जाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ई-डीपीआर के माध्यम से डीपीआर तैयार किए जाने से लेकर सरकार तक पहुंचने तक की गतिविधि ई-डीपीआर के माध्यम से की जाए। उन्होंने कहा कि ई-डीपीआर का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को शत-प्रतिशत रूप से ऑनलाईन किया जाए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि यूकेपीएफएमएस के माध्यम से सभी कर्मियों की सर्विस बुक डाटा को अपडेट किया जाए।

उन्होंने कहा कि आईएफएमएस डेटा का डिजिटाईजेशन शीघ्र किया जाए। इसके लिए आईएफएमएस मैकेनिज्म को मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने

सभी विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं वाहन चालकों के जीपीएफ सम्बन्धी डेटा को भी लगातार अपडेट किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र कर्मियों की चयन वर्ष में पदोन्नति अनिवार्य रूप से 1 जुलाई को कर ली जाए, ताकि कार्मिकों को पदोन्नति में वर्ष का नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही का नुकसान कार्मिकों को नहीं होना चाहिए।

मुख्य सचिव ने सभी सचिवगणों को अपने-अपने विभागों के अंतर्गत 100 प्रतिशत ई-ऑफिस शीघ्र लागू किए जाने के निर्देश दोहराए। उन्होंने जनपद स्तरीय कार्यालयों को भी शीघ्र ई-ऑफिस पर शिफ्ट किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, विभागों में 100 प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा जिलाधिकारियों को अलग-अलग दिन अलग-अलग समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित कर के अनावश्यक रूप से व्यस्त रखा जाता है। इस समस्या के निस्तारण एवं जिलाधिकारियों को अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए मुक्त रखे जाने हेतु शुक्रवार सायंकाल का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त जिन भी विभागों को जिलाधिकारियों के साथ बैठक करनी हैं, वे प्रत्येक शुक्रवार सायंकाल जिलाधिकारियों के साथ आयोजित होने वाली बैठक में अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी बैठकों के एजेण्डा पॉइन्ट्स पूर्व में ही जिलाधिकारियों को साझा किए जाएं। मुख्य सचिव ने शीघ्र ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नियुक्ति के कार्यक्षेत्र (विकासखण्ड, तहसील और जिला मुख्यालय) को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने विभागों के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, राधिका झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चैधरी, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चैहान एवं धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कुम्भ मेले की तैयारियों को लेकर सीएस ने ली बैठक

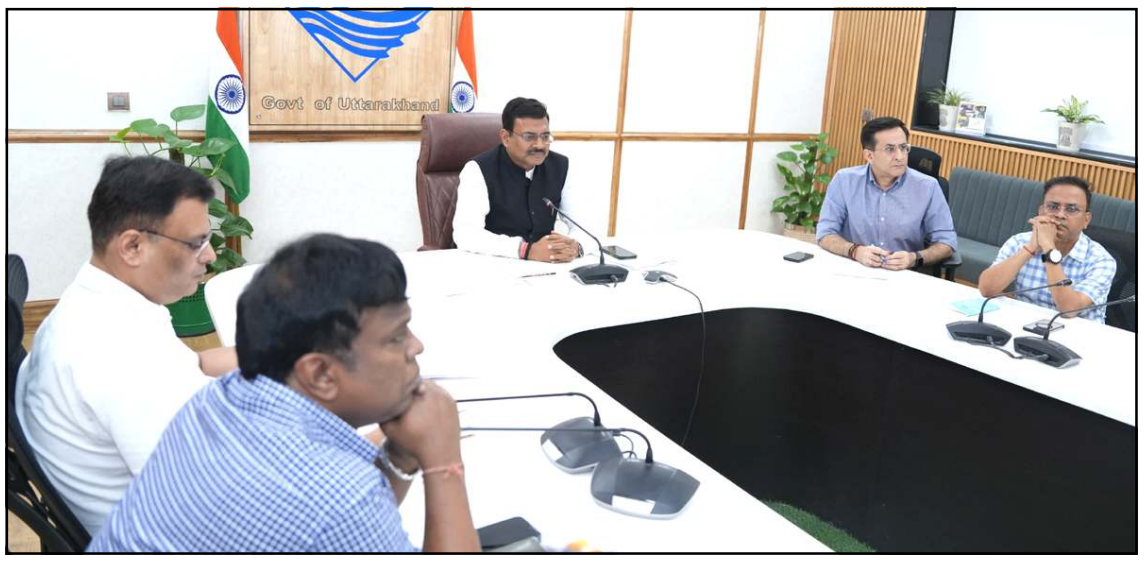

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली।

मुख्य सचिव ने कहा कि 2027 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के दृष्टिगत सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति के कार्य 31 अक्टूबर, 2026 तक पूर्ण कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि कार्य समाप्ति की अंतिम तिथि को गंभीरता से लेते हुए सभी कार्यों को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों के नोडल अधिकारी शीघ्र नामित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रमुख स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या का आंकलन कर उसके अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुरूप ही घाटों की संख्या भी बढ़ाई जाए। उन्होंने मेलाधिकारी को सभी हितधारकों से लगातार संवाद करते हुए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टेक्निकल ऑडिट कमिटी और थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने कुम्भ मेले के लिए सभी प्रकार के कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए ए, बी, सी श्रेणियों में बांटे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों को प्रत्येक स्थिति में कराया ही कराया जाना है, ऐसे कार्यों के लिए तत्काल कार्यवाही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दीर्घावधि के कार्यों को भी प्राथमिकता पर लिया जाए, ताकि वे समय से पूर्ण हो सकें। उन्होंने अस्थायी प्रकृति के कार्यों को समयावधि के अनुरूप कराए जाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने कहा कि जिन-जिन विभागों एवं संस्थाओं को कुम्भ मेला क्षेत्र में स्थान आवंटित किया जाता है, उन स्थानों पर यदि अतिक्रमण हो रखा है तो, अतिक्रमण हटाते हुए विभागों को आवंटित किया जाए। उन्होंने कुम्भ मेला क्षेत्र में सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने एसपी हरिद्वार को कुम्भ मेले के दौरान यातायात एवं पार्किंग प्लान 20 अगस्त, 2025 तक मेलाधिकारी को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग, पेयजल एवं विद्युत विभाग सहित अन्य सभी ऐसे विभागों, जो कुम्भ मेले के दौरान सेवाएं देते हैं, को अपनी कार्ययोजना भी 20 अगस्त, 2025 तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश द्वारा मरम्मत के लिए नहर बंदी के समय जो कुम्भ मेले से सम्बन्धित कार्य उत्तराखण्ड द्वारा कराए जाने हैं, उसके लिए पूर्व से ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, ताकि नहरबंदी के दौरान तत्काल कार्य कराया जा सके।

मुख्य सचिव ने कुम्भ मेला क्षेत्र को बढ़ाए जाने की सम्भावनाएं तलाशे जाने पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी प्रकार की सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने हेतु उच्चाधिकारियों को क्षेत्रीय भ्रमण कर समय से कार्य पूर्ण कराए जाएं। मुख्य सचिव ने रानीपुर मोड़, रेलवे पुल से ज्वालापुर तक जल भराव की समस्या का भी हल निकाले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत कुम्भ मेला क्षेत्र में अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ही विभिन्न जगहों पर फायर हाइड्रेंट भी स्थापित किए जाएं।

इस अवसर पर मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कुम्भ मेले के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इस अवसर पर डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री नितेश कुमार झा, श्री बृजेश कुमार संत, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, श्री युगल किशोर पंत एवं डॉ . रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जिलाधिकारी हरिद्वार, देहरादून, टिहरी और पौड़ी भी उपस्थित थे।

सीएम ने यूपी व उत्तराखण्ड के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की

देहरादून(नवल टाइम्स)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन मामलों में दोनों राज्यों के बीच पिछली बैठक में सहमति बनी थी, उनमें से जिन मामलों में कार्यवाही गतिमान है, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनका जल्द समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों राज्यों के अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामले में जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक करेंगे।

दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पिछली बैठक के बाद जिला उधमसिंहनगर एवं हरिद्वार में स्थित जलाशयोंध्नहरों में वाटर स्पोर्टस की अनुमति दी जा चुकी है। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विद्युत बिलों के रूप में 57.87 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम द्वारा उत्तराखण्ड मत्स्य पालन विकास अभिकरण को 3.98 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। वन विकास निगम उत्तराखण्ड को दी जाने वाली देयताओं का आंशिक भुगतान किया गया है। परिवहन निगम की अवशेष राशि का भुगतान किया गया जा चुका है। आवास

विभाग के अन्तर्गत आवास विकास परिषद की परिसम्पत्तियों के निस्तारण का निर्णय हुआ है। बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. नीरज खेरवाल एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

स्वाभिमान मोर्चा का डिजिटल और जमीनी ढांचा और मजबूत

देहरादून। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों एवं राज्य में जनविकल्प की व्यापक रणनीति के तहत संगठन विस्तार करते हुए केंद्रीय कार्यकारिणी में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ की हैं। मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी ने ऋषिकेश से महापौर पद के पूर्व उम्मीदवार एवं विभिन्न आंदोलन से जुड़े वरिष्ठ नेता दिनेश चंद्र मास्टर को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का संगठन प्रभारी नियुक्त किया है। मास्टर जी ने पूर्व में भी पार्टी को धरातल पर मजबूती देने में अग्रणी भूमिका निभाई है और मूल निवास एवं भू कानून जैसे मुद्दों पर उनकी स्पष्ट दृष्टि रही है। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों पर संगठन की पहुंच और जनजुड़ाव को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मनोज कोठियाल को सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। मनोज कोठियाल डिजिटल रणनीति, जनभावनाओं की अभिव्यक्ति और राज्यहित के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने में माहिर माने जाते हैं। सोशल मीडिया टीम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आशुतोष कोठारी एवं समीर सजवाण को सोशल मीडिया सहप्रभारी नियुक्त किया गया है।

कानूनी सलाहकार

एड. अनुज कुमार शर्मा

चैम्बर नं. 20, रोशनाबाद

हरिद्वार (उत्तराखंड)

मो. 9837387718

मानसून सीजन को लेकर सजग रहें विभागीय अधिकारी : महाराज

देहरादून(नवल टाइम्स)। मानसून के दौरान सड़कों के अवरुद्ध होने से बड़ी संख्या में लोग मार्ग खुलने की घंटों प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे में हमें सजग रहना चाहिए और सड़कों को खोलने में तत्परता दिखानी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही लक्ष्य है कि हम पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करें और मानसून के दौरान यात्रा में जो अवरोध आते हैं उसका तत्काल समाधान हो। उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को यमुना कालोनी, स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय लोक निर्माण विभाग सभागार में उपस्थित लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ मानसून सीजन की तैयारीयों के संबंध में हुई समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि यदि हम सजगता के साथ काम करेंगे तो मानसून का सीजन बिना किसी अवरोध के ठीक से निकल जायेगा। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान यदि कोई सड़क बंद होती है तो उसकी पूर्व

सूचना यात्रियों को पहले ही पूर्ववर्ती स्टेशन पर मिल जानी चाहिए ताकि वह वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर अपने गंतव्य तक पहुंच सके।

श्री महाराज ने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए की मानसून के दौरान सड़कों पर जेसीबी की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले नालों की साफ सफाई तथा पानी की उचित निकासी के प्रबंधन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात से राज्य में 54 सड़कें अवरुद्ध थी जिनमें से 19 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 672 सड़कें पूरी तरह से खुली हुई हैं। मानसून के दौरान मार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में इस समय 361 वैकल्पिक मार्ग यातायात के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए की मैदानी क्षेत्रों में अधिकतर स्थानों पर बाढ़ एवं जल भराव का खतरा हमेशा बना रहता है इसलिए ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। बैठक के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने सिंचाई मंत्री को बताया कि मानसून अवधि तक प्रत्येक जनपद के नोडल खण्ड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी गई हैं। सिंचाई खण्ड, देहरादून के परिसर में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया जा चुका है। बाढ़ सम्बन्धित सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु विभागीय बाढ़ नियंत्रण प्रभारी द्वारा एक ंजेश्ंचच ळतवनच बनाया गया है, जिसमें राज्य/जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य हैं तथा सभी अधिकारी मोबाईल पर 24X7 हमेशा उपलब्ध हैं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजीव शर्मा ने किरण ऑफसेट प्रिटिंग प्रेस, निकट गुरूकुल कांगड़ी फार्मेसी, कनखल, हरिद्वार (उत्तराखंड) से छपवाकर, म.नं. डी-31/2 आदर्शनगर कालोनी, गोल गुरूद्वारा, सेंटमेरी स्कूल के पीछे, ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड) से प्रकाशित किया।

: सम्पादक :

संजीव शर्मा

मो. 8057605991/9897106991

ईमेल: navaltimes@gmail.com

सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार होगा

प्रबंध संपादक

डा. संदीप भारद्वाज

बिजनौर प्रभारी

विशाल शर्मा

सभी पद अवैतनिक हैं